

संपत्ति-कर आयुक्त

बनाम

महादेव जालान और महावीर प्रसाद जालान

13 सितंबर, 1972

[पी. जगनमोहन रेड्डी और एच. आर. खन्ना, जे. जे.]

धन कर अधिनियम, 1957-धारा 7-में शेयरों के मूल्यांकन का आधार प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ।

संपत्ति-कर अधिनियम, 1957 की धारा 7 के प्रयोजन के लिए निजी सीमित कंपनियों में शेयरों के मूल्यांकन का आधार क्या है, के प्रश्न पर -
निर्णीत:- चालू संस्था में मूल्यांकन का सामान्य सिद्धांत औसत बनाए रखने योग्य लाभ के आधार पर उपज, समायोजन आदि के अधीन, जिसके लिए किसी विशेष मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता हो सकती है। एक सीमित कंपनी में शेयरों के मूल्यांकन के विभिन्न पहलुओं की जांच से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलेंगे:

(क) जहाँ किसी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत किया जाता है और अवधि में सौदे होते हैं, मूल्यांकन तिथि पर प्रचलित मूल्य शेयरों का मूल्य होता है।

(ख) जहाँ शेयर एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत नहीं हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हैं, मूल्यांकन का निर्धारण उचित वाणिज्यिक आधार पर लाभ अर्जित करने की क्षमता को दर्शाने वाले लाभांश के संदर्भ में किया जाता है। लेकिन जहां वे नहीं करते हैं, तो उस आधार पर उपज की राशि शेयरों का मूल्य निर्धारित करेगी। दूसरे शब्दों में, कंपनी जो लाभ कमा रही है और उसे अर्जित करना चाहिए, वह सामान्य रूप से मूल्य निर्धारित करेगा। लाभांश और अर्जित करने की विधि या उपज विधि पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं; दोनों को लाभ अर्जित करने की क्षमता का पता लगाने में मदद करनी चाहिए। यदि दोनों तरीकों के परिणाम अलग-अलग होते हैं, तो एक मध्यवर्ती आंकड़े की गणना अनुचित खर्चों के समायोजन और लाभ के उचित हिस्से को अपनाकर करनी पड़ सकती है।

(ग) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मामले में भी जहाँ खर्च वाणिज्यिक उद्यम के सभी अनुपात में वहन किए जाते हैं, उन्हें उपज की गणना में कंपनी के लाभ में वापस जोड़ा जाएगा। ऐसी कंपनियों में शेयर हस्तांतरण पर प्रतिबंध को भी मूल्यांकन पर पहुंचने में ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) जहाँ लाभांश प्राप्ति और अर्जित करने की विधि कंपनी की लाभ अर्जित करने और लाभांश घोषित करने में असमर्थता के कारण विभाजित होती है- यदि सेटबैक अस्थायी है, तो सेटबैक से पहले शेयरों के मूल्यों का

अनुमान लगाना संभाव है और उन कंपनियों के उद्धृत शेयरों की कीमत में आनुपातिक गिरावट के अनुरूप प्रतिशत की छूट देना संभव है, जिन्हें समान उलटफेर का सामना करना पड़ा है।

(ई) जहां कंपनी बंद होने की कगार पर है, विभाजन मूल्य पद्धति निर्धारित करती है कि उस प्रक्रिया से क्या प्राप्त होगा।

(च) जैसा कि सीलोन के महान्यायवादी बनाम मैकी में परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यांकन उचित होगा, जब जहां उस स्थिति में मुनाफे में उतार-चढ़ाव और मूल्यांकन की तिथि पर परिस्थितियों की अनिश्चितता संभावित लाभ और लाभांश के उचित अनुमान को रोके।

उपरोक्त सिद्धांतों को स्थापित करने में, हमने कोई कठोर नियम बनाने की कोशिश नहीं की है क्योंकि अंततः प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, व्यवसाय की प्रकृति, लाभप्रदता की संभावनाएं और ऐसे अन्य विचारों को ध्यान में रखना होगा, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर लागू होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, बाजार मूल्य जब तक कि असाधारण परिस्थितियों में, जिनका हमने उल्लेख किया है, इस परिकल्पना पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक धारक कम्पनी को परिसमापन में ला सकता है, इसका मूल्य परिसमापन पर माना जाना चाहिए विभाजन मूल्य पद्धति, उपज विधि, आम तौर पर लागू विधि है जबकि विभाजन मूल्य पद्धति वह है जिसका

असाधारण परिस्थितियों में सहारा लिया जाता है या जहां कंपनी परिसमापन के लिए तैयार है लेकिन फिर भी यह तरीकों में से एक है।

सीलोन के महान्यायवादी बनाम मैकी [1952] 2 आल ई.आर. 775 पी. सी., स्मिथ बनाम राजस्व आयुक्त, 1931 आयरिश रिपोर्ट 643, मैक कैथी वी. कराधान के संघीय आयुक्त, 69 राष्ट्रमंडल कानून रिपोर्ट पृष्ठ 1 और फेडरल कमिश्नर ऑफ टैक्सेशन v. सागर, 71 सी. एल. आर. 422 संदर्भित किया गया।

(3) इस न्यायालय के पास उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए प्रश्न को तब तक फिर से तैयार करने की शक्ति है जब तक कि कोई नया और अलग सवाल नहीं उठाया जाता है, लेकिन इसे केवल न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्न को फिर से तय करने या फिर से तैयार करने तक ही सीमित रखे ताकि पार्टियों के बीच वास्तविक मामले को सामने लाया जा सके।

नारायण स्वदेशी वीविंग मिल्स बनाम ई.पी.टी. आयुक्त, 26 आई.टी.आर. 765 के 774 में और कुसुम बेन डी महादविया बनाम आयकर आयुक्त, 544 पर 39 आई.टी.आर. 540 निर्दिष्ट।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 1135 और 1136/1969.

निर्णय और आदेश दिनांकित 12 दिसंबर 1967 में विशेष अनुमति अपील असम और नागालैंड उच्च न्यायालय, गुवाहाटी 1966 के संपत्ति कर संदर्भ संख्या 3 व 4 में।

और

1969 की सिविल अपील सं 1765 से 1767 तक।

1965 के दीवानी नियम सं. 6 (एम) में गुवाहाटी के असम और नागालैंड उच्च न्यायालय के 4 फरवरी 1969 के निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील,

वेद व्यास, बी. बी. आहूजा, एस. पी. नायर और आर. एन. सचथे.....अपीलार्थी की और से।

एम. सी. सीतलवाड़ और एस. सी. मजूमदार.....
उत्तरदाताओं की और से।

न्यायालय का निर्णय जगनमोहन रेडडी के द्वारा दिया गया था

ये अपीलें असम और नागालैंड उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा हैं। 1969 की अपील संख्या 1136 महादेव मृगेंद्र जालान की है, जो महादेव प्रसाद द्वारा हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता के रूप में है, जबकि 1969 की अपील संख्या 1135 उनकी व्यक्तिगत क्षमता में है। इन दोनों अपीलों में, हिंदू अविभाजित परिवार के साथ-साथ व्यक्ति के पास पांच कंपनियों में शेयर थे, जिनके संबंध में शेयरों, लाभांश की घोषणा

की जा रही थी। संपत्ति-कर अधिकारी ने विभाजन मूल्य के आधार पर उन शेयरों के मूल्यांकन की गणना की और उन्हें अपनी कुल संपत्ति में शामिल किया।

अपील संख्या 1765, 1766 और 1767/1969 प्रतिवादी क्रमशः महाबीर प्रसाद जालान, महादेव जालान और मदन मोहन जालान। ये अपीलें निर्धारण वर्ष 1957-58 और 1958-59 से संबंधित हैं। इन वर्षों के संबंध में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के शेयरों का मूल्य उनकी उपज के आधार पर संबंधित निर्धारितियों की कुल संपत्ति में शामिल किया गया था, हालांकि कुछ कंपनियां लाभांश का भुगतान नहीं कर रही थीं जबकि अन्य पूरे समय लाभांश की घोषणा कर रही थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहली दो अपीलें, जो बाद के वर्ष से संबंधित थीं, उच्च न्यायालय द्वारा सुनी गईं और 12 दिसंबर, 1967 को निपटा दी गईं, जबकि मुख्य रूप से पहली दो अपीलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर पिछली तीन अपीलों का निपटारा बाद में 4 फरवरी, 1969 को किया गया। ऊपर उल्लिखित तीन व्यक्तियों से संबंधित निर्धारण वर्ष 1957-58 और 1958-59 के लिए, संपत्ति कर कार्यालय ने, वर्ष 1959-60 के मूल्यांकन के मामले में, शेयरों के विभाजन मूल्य को अपनाया था जैसा कि कंपनी की तुलन-पत्र पर उनके मूल्य की गणना करने में खुलासा किया गया था। ऐसा लगता है जैसे कि प्रत्येक कंपनी को परिसमापन के लिए लाया गया था। इस मूल्यांकन की पुष्टि अपीलीय सहायक आयुक्त ने की। न्यायाधिकरण ने हालांकि माना कि

निश्चित रूप से यह आधार निजी कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन के मान्यता प्राप्त तरीकों में से एक है जो खुले बाजार में बिक्री योग्य नहीं हैं, लेकिन जहां तक उन मामलों का संबंध है, शेयरों से प्राप्त उपज के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। शेयरों से उनके संबंधित मामलों की विशेष परिस्थितियों में अपनाया जाने वाला एक अधिक उचित तरीका होगा। तदनुसार, उन्होंने अपने आदेश में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी के संबंध में उस आधार पर मूल्यांकन को अपनाया। पहले दो अपीलों में भी संपत्ति कर अधिकारी और अपीलीय सहायक आयुक्त ने अन्य मामलों की तरह विभाजन मूल्य को आधार के रूप में अपनाया, और उस आधार से सहमत हुए, क्योंकि निर्धारित संबंधित कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश से संबंधित तथ्य और आंकड़े संपत्ति कर अधिकारी और अपीलीय सहायक आयुक्त के सामने रखने में विफल रहे थे। न्यायाधिकरण द्वारा यह भी कहा गया था कि पिछले तीन अपीलों के मामले में न्यायाधिकरण द्वारा सुनवाई के समय, यह स्पष्ट रूप से न्यायाधिकरण के ध्यान में नहीं लाया गया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होने के कारण घोषित लाभांश को नियंत्रित किया जाएगा। कंपनियों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने स्वयं के उद्देश्य के अनुरूप, घोषित लाभांश के बजाय रखरखाव योग्य लाभ उचित आधार प्रदान करेगा। ऐसा बताते समय, यह देखा गया कि मामले के इस पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे समक्ष आपत्ति केवल इस सिद्धांत पर है कि "विभाजन मूल्य" पद्धति को अपनाया जाए या

नहीं। इसलिए पहली दो अपीलों के संबंध में न्यायाधिकरण ने माना कि विभाजन मूल्य को अपनाना उचित था।

धारा-66(1) के तहत एक आवेदन पर न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित प्रश्न को उच्च न्यायालय की राय के लिए संदर्भित किया, अर्थात्,

"क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में आयकर न्यायाधिकरण द्वारा विचाराधीन शेयरों के मूल्यांकन के आधार के रूप में अपनाया गया 'विभाजन' मूल्य का सिद्धांत कानून में टिकाऊ है?"

जब यह संदर्भ उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो यह महसूस किया गया कि प्रश्न के लिए एक सारगर्भित उत्तर की आवश्यकता है कि क्या 'विभाजन मूल्य' का सिद्धांत कानून में टिकाऊ है और जैसा कि उनकी राय में न्यायाधिकरण न्यायालय की राय का उल्लेख करना चाहता था

"मामले से निपटने में उन्हें जो संदेह हुआ, वह इस सवाल से संबंधित था कि क्या 'विभाजन मूल्य' पद्धति मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली सही पद्धति है या यह अपनाई जाने वाली 'उपज मूल्य' पद्धति है, उस प्रश्न को दोबारा तैयार किया गया और न्यायाधिकरण से

मामले का एक और विवरण मांगा गया। दोबारा तैयार किया गया प्रश्न इस प्रकार है:--

"क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर न्यायाधिकरण को संपत्ति कर अधिनियम की धारा 7 के तहत विचाराधीन शेयरों का मूल्य निर्धारित करने में 'उपज मूल्य' के सिद्धांत को शामिल करने वाली विधि के बजाय 'विभाजन' मूल्य के सिद्धांत को शामिल करने वाली विधि का पालन करना कानूनी रूप से उचित था?"

इस निर्देश के अनुपालन में न्यायाधिकरण ने मामले का एक पूरक बयान तैयार किया और इसे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया। उस बयान में न्यायाधिकरण ने कहा:

"ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष मूल्यांकन के किसी वैकल्पिक आधार का दावा नहीं किया गया है। न्यायाधिकरण के समक्ष पहली बार, निर्धारिती ने वर्ष 1953 से 1957 के दौरान उपरोक्त निजी कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश का एक विवरण दायर किया और दावा किया कि शेयरों का बाजार मूल्य प्रत्येक कंपनी द्वारा घोषित लाभांश के औसत प्रतिशत के संदर्भ में और इस आधार पर

निकाला जाना चाहिए कि बाजार में 100 रुपये प्रति शेयर पर उद्धृत शेयरों पर रु. 6/- लाभांश मिलेगा।"

न्यायाधिकरण द्वारा आगे कहा गया कि निर्धारिती ने मूल्यांकन वर्ष 1957-58 और 1958-59 के लिए न्यायाधिकरण के निर्णय पर भरोसा किया था, जहां उसने उपज के आधार पर शेयरों का बाजार मूल्य निर्धारित किया था, लेकिन जहां तक मूल्यांकन वर्ष की बात है 1959-60 में मैंने यह स्वीकार नहीं किया कि इससे पहले दी गई जानकारी "रखरखाव योग्य मुनाफे" के आधार पर बाजार मूल्य निकालने के लिए पर्याप्त होगी क्योंकि उनका विचार था कि "निजी कंपनियों के मामलों में लाभांश की घोषणा किसके द्वारा तय की जाएगी" निदेशक अपने व्यक्तिगत मूल्यांकन में लाभ को ध्यान में रखते हैं न कि क्षमता या अन्य व्यावसायिक विचारों के संदर्भ में। यह कहा गया कि

" 'रखरखाव योग्य मुनाफा' कंपनी द्वारा देय करों की कटौती के बाद कंपनी के शुद्ध मुनाफे का एक निश्चित प्रतिशत (मान लीजिए 80%) होगा और यह प्रति शेयर संभावित उपज का एक उपाय होगा।"

इस दृष्टि से पहली दो अपीलों में 1959-60 के आकलन के संबंध में आयकर अधिकारी द्वारा अपनाए गए 'विभाजन' मूल्य की पुष्टि की गई थी।

हालाँकि, उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए आधार से सहमत नहीं था, हालाँकि उसने माना कि गणना के उद्देश्य के लिए विभाजन मूल्य भी तरीकों में से एक है। निर्धारिती की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि 'विभाजन' मूल्य पद्धति केवल उस कंपनी पर लागू की जाएगी जो परिसमापन और समापन के चरण में पहुंच गई है। संबंधित तर्कों और उसके समक्ष संदर्भित निर्णयों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

"हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जहां तक संपत्ति कर अधिनियम की धारा-7 के अनुप्रयोग का संबंध है किसी मृत्यु व्यक्ति के शेयरों का मूल्य उसकी मृत्यु के आंकड़ों पर निर्धारित करने का संबंध है, जहां वे शेयर एक चल रही संस्था से संबंधित हैं, अपनाने का एकमात्र उचित तरीका 'उपज मूल्य' विधि था और हमारा मानना है कि न्यायाधिकरण का यह मानना उचित नहीं था कि एक निजी कंपनी के मामले में लाभांश को कंपनी को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप नियंत्रित किया जाएगा, और परिणामस्वरूप, 'रखरखाव योग्य लाभ' आधार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये न कि लाभांश के रूप में। जब तक न्यायाधिकरण के सामने कोई अलग निष्कर्ष

निकालने के लिए कोई ठोस सामग्री न हो, हमारी राय में, न्यायाधिकरण का ऐसा करना उचित नहीं है।

हम इस बात पर ध्यान देने के लिये विवश हैं कि यद्यपि न्यायाधिकरण ने पिछले वर्षों के संबंध में अपने निर्णयों में 'उपज मूल्य' पद्धति को अपनाया था, लेकिन न्यायाधिकरण ने एक नया मार्ग अपनाया था और मूल्यांकन के आधार के रूप 'विभाजन' मूल्य पद्धति को अपनाया था। हमें लगता है कि गणना में अपनाई जाने वाली पद्धति में इस बदलाव को उचित ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है।"

जब धारा-66 (2) के तहत पिछली तीन अपीलों के संबंध में धारा-66(1) के तहत एक आवेदन के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष आया, को न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया था, यह पाया गया :-

"यह निस्संदेह कानून का प्रश्न है लेकिन इसका जवाब 9 जून, 1967 के इस न्यायालय के निर्णय में शामिल होगा..."

और इसलिए उसने न्यायाधिकरण से उसी बिंदु को फिर से संदर्भित करने के लिए कहना अनावश्यक समझा और तदनुसार याचिकाओं को खारिज कर दिया। पहली दो अपीलों के संबंध में विशेष अनुमति उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि 'उपज पद्धति'

एक उचित पद्धति थी और बाद की तीन अपीलों के संबंध में न्यायाधिकरण को एक मामला बताने का निर्देश देने से इंकार करने वाले आदेश के खिलाफ है। चूंकि सामान्य प्रश्न को निर्धारित करना होगा, इन अपीलों को समेकित किया जाएगा और एक साथ सुना जाएगा।

इस मामले में जो प्रश्न निर्धारित किया जाना है वह यह है कि संपत्ति कर अधिनियम (1957 का 27) की धारा-7 के प्रयोजनों के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में शेयरों के मूल्यांकन का आधार क्या है। धारा-7 की उपधारा (1) में प्रावधान है कि

"इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नकदी के अलावा किसी भी संपत्ति का मूल्य, उस मूल्य के रूप में अनुमानित किया जाएगा जो संपत्ति कर अधिकारी की राय में खुले बाजार में मूल्यांकन पर बेचे जाने पर प्राप्त होगा।"

मूल्यांकन की तारीख, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, कैलेंडर वर्ष की 31 दिसंबर है। उस तिथि पर संपत्ति-कर अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि खुले बाजार में बेचे जाने पर शेयरों का क्या मूल्य होगा जो एक इच्छुक विक्रेता स्वीकार करेगा और एक इच्छुक खरीदार भुगतान करेगा।

किसी लिमिटेड कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन करते समय कुछ कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले, एक शेयर धन की राशि

नहीं है, बल्कि धन की राशि से मापा जाने वाला एक ब्याज है और एसोसिएशन के लेखों में निहित विभिन्न अधिकारों से बना है। वे अलग-अलग श्रेणियों के होते हैं जैसे इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर, पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयर या आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर। इनके अलावा ऋणपत्र भी हैं। शेयर पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो सकते हैं और बाद के मामले में वे कुछ प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। एक निजी कंपनी को कंपनी अधिनियम की धारा-3(iii) में परिभाषित किया गया है, जो अपने अनुच्छेदों द्वारा

(ए) अपने शेयरों को स्थानांतरित करने के अधिकार, यदि कोई हो, को प्रतिबंधित करती है, ;

(बी) अपने सदस्यों की संख्या को 50 तक सीमित करती है, जिसमें उस खंड के (i) और (ii) में निर्दिष्ट कुछ श्रेणियां शामिल नहीं हैं और

(सी) कंपनी के किसी भी शेयर या ऋणपत्र की सदस्यता के लिए जनता को किसी भी निमंत्रण पर प्रतिबंधित करती है। शर्त यह है कि संयुक्त रूप से रखे गए शेयरों को ऐसे माना जाएगा जैसे कि वे एक ही सदस्य के पास हैं। धारा-3(iv) के अधीन एक सार्वजनिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है। यह देखा जा सकता है कि एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी से अलग करने वाली तीन शर्तें संचयी हैं और यदि इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं होती है तो कंपनी एक

सार्वजनिक कंपनी होगी। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां कंपनी के लेखों के तहत शेयरों को स्थानांतरित करने का अधिकार अन्य सदस्यों को पहले से तय कीमत पर या निर्धारित तरीके से पेश किए बिना प्रतिबंधित है, या जहां निदेशकों के पास स्थानांतरण पर वीटो करने की शक्ति होती है, शेयर के मूल्य का निर्धारण करना होगा हस्तांतरण के प्रतिबंध को नजरअंदाज किए बिना निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि वे संपत्ति में एक अंतर्निहित तत्व हैं जिसका मूल्य निर्धारण किया जाना है। यह प्रतिबंध आवश्यक रूप से अपमानजनक नहीं हो सकता है क्योंकि लाभप्रद शर्तों पर कंपनी में अन्य सदस्यों के शेयरों को प्राप्त करने का मौका अपने आप में एक लाभ ही है। ऐसे मामलों में जहां शेयरों का मूल्यांकन कंपनी की संपत्ति के संदर्भ में किया जाना है, अलगाव पर प्रतिबंध अप्रासंगिक हैं।

जिन शेयरों का हस्तांतरण प्रतिबंधित नहीं है, उन्हें उन स्टॉक एक्सचेंजों पर बेचा जा सकता है जिनके लिए आधिकारिक बाजार उद्घरण है। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयर भी हो सकते हैं जिनके लिए स्टॉक एक्सचेंज पर कोई कोटेशन नहीं है। सामान्यतः वह मूल्य, जिस पर एक उचित रूप से इच्छुक खरीदार शेयर खरीदेगा, एक काल्पनिक खरीदार को अभिनिर्धारित करता है लेकिन ऐसे मामले में भी यह माना जा सकता है कि विक्रेता केवल उसके वास्तविक मूल्य के लिए शेयर बेचने को तैयार होगा और खरीददार कीमत चुकाने को तैयार होगा। इसे सदैव वैचारिक रूप

से निर्धारित किया जाना चाहिये। जहां किसी कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लाए और बेचे जाते हैं और बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाली कोई असामान्यता नहीं होती है, तो व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में शेयर जिस कीमत पर हाथ बदल रहे होते हैं, वह आमतौर पर उनका वास्तविक मूल्य होता है। ये कोटेशन आम तौर पर कई कारकों को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्ति के मूल्य को दर्शाते हैं, जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार करने वाले व्यक्तियों और उन खरीददारों द्वारा ध्यान में रखा जाता है जो किसी विशेष शेयर या शेयरों में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। यहां तक कि जहां उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत किया जाता है, वहां उद्धरण पूरी तरह से उपज या घोषित लाभांश पर निर्भर नहीं होते हैं। ऐसे कई कारक हैं जिन पर विचार किया जाता है जो उद्धरण को प्रभावित और निर्धारित करते हैं, अर्थात् वे कारक जिन पर एक व्यक्ति द्वारा विचार किया जाता है जो अपने शेयर बेचना चाहता है और वे कारक जिन्हें एक खरीदार जो उन्हें खरीदना चाहता है उन्हें निर्धारित करने के रूप में मानता है। वह मूल्य जो क्रेता भुगतान करने को तैयार है और विक्रेता प्राप्त करने को तैयार है। किसी भी संकटपूर्ण बिक्री को छोड़कर, हमारे विचार में जो कारक किसी विशेष दिन या किसी विशेष समय पर किसी शेयर के निर्धारण को निर्धारित करने की संभावना रखते हैं, वह है, सबसे पहले, उचित वाणिज्यिक आधार पर कंपनी की लाभ कमाने की क्षमता; दूसरे, उन मुनाफों या निवेशित पूंजी के लिए उचित रिटर्न को बनाए रखने की इसकी

क्षमता, और निवेश कंपनियों जैसे विशेष मामलों में, परिसंपत्ति-समर्थन; बोनस शेयरों की घोषणा के रूप में अपनी कमाई के पूंजीकरण की संभावनाएं या जहां कंपनी वित्तीय और व्यावसायिक रूप से मजबूत है। अतिरिक्त पूंजी जारी करने की संभावनाएं जहां मौजूदा शेयरधारकों को एक निश्चित कीमत पर आवेदन करने और उन्हें प्राप्त करने का अधिकार है, जो आम तौर पर बाजार मूल्य से कम है, अपने निवेश पर बढ़े हुए लाभ की पेशकश करते हुये, यह धारणा कि कंपनी समान दर बनाए रखने में सक्षम होगी या कम से कम लाभांश के कुल भुगतान को बढ़ाएगी- बढ़ी हुई पूंजी पर निर्भर करता है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि नए शेयर निर्गम, चाहे कोई मौजूदा शेयरधारक उनकी सदस्यता लेता है या नहीं, लागत पर उसके औसत लाभ की दर में परिणामी वृद्धि के साथ उसकी कुल हिस्सेदारी की औसत इकाई लागत को हमेशा कम कर देता है।

उस व्यक्ति का मामला लीजिए जो किसी विशेष कंपनी में शेयर खरीदना चाहता है। यदि उसका उद्देश्य केवल निवेश करना है, तो वह पूछताछ कर सकता है कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनमें अच्छी संभावनाएं हैं और अच्छा निवेश है, जिन्हें अक्सर "अपराध धारित प्रतिभूतियों के रूप में जाना जाता है। इसमें यह पता लगाना शामिल होगा कि जिस कंपनी में वह निवेश करने का इरादा रखता है वह वित्तीय और व्यावसायिक रूप से मजबूत है या नहीं, क्या वह जो पूंजी निवेश करेगा उस पर कितना लाभ मिलेगा, क्या वह लाभ कायम रहेगा, क्या शेयरों की

कीमत बढ़ेगी मूल्य में हैं और जब भी वह उनका निपटान करना चाहता है तो आसानी से विपणन योग्य होते हैं। कुछ मामलों में कोई व्यक्ति उन शेयरों में निवेश करके जोखिम उठाना चाह सकता है जिनमें वाणिज्यिक दुनिया और किसी विशेष उद्योग में विभिन्न रुझानों को ध्यान में रखते हुए सुधार की संभावनाएं हैं और शेयरों का मूल्य निवेश की गई पूंजी पर प्राप्त लाभ या लाभ के अनुरूप लाभ के साथ बढ़ रहा है, जो उसे अन्य मजबूत परिसंपत्तियों में मिलने वाले लाभ की तुलना में बहुत अधिक है। अभी भी ऐसे निवेशक हो सकते हैं जो इस बात के बावजूद कि कंपनी एक विलायक स्थिति में नहीं है या कई वर्षों तक लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ है, हेरफेर के उद्देश्य से नियंत्रित ब्याज खरीदने या इससे कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए परिसमापन में लाने के इच्छुक हैं। ऐसे मामलों को नजरअंदाज करते हुए, जहां कोई खरीदार या विक्रेता किसी कंपनी में शेयरों की खरीद या बिक्री के लिए विभिन्न कारकों पर विचार कर रहा है, तो वह जो कीमत चुकाएगा या प्राप्त करेगा, उसका निर्धारण करने वाला प्रमुख कारक उपज है।

अब, वे कौन से कारक हैं जिन पर एक विक्रेता ध्यान देगा जब वह अपने शेयर बेचना चाहेगा? जहां वह बेचने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत नहीं है, वह पहले इस बात पर विचार करेगा कि क्या उसे जो रिटर्न मिल रहा है वह मौजूदा बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए उचित है। यहां फिर से उपज का कारक उसके विचार में उस पूंजी पर नहीं

बल्कि उस पर केंद्रित होगा जो उसने शुरू में निवेश किया था, बल्कि उस पर जो वह बिक्री पर प्राप्त होने की उम्मीद करता है, उसके पास एक बेहतर निवेश हो सकता है जो उस पर अधिक उपज देगा या उसकी पूंजी के लिए बेहतर संभावनाएं सुनिश्चित करेगा। ऐसा हो सकता है कि उसे उच्च लाभांश बनाए रखने की उम्मीद न हो या इन लाभांशों के कम होने की संभावना हो या पूंजी की सुरक्षा खतरे में पड़ने की संभावना हो, और इसलिए वह विवेकपूर्ण बिक्री करना चाहता हो। हमने जो कहा है, उन कारकों में से जो खरीदार और विक्रेता के विचार को नियंत्रित करते हैं, जहां एक खरीदना चाहता है और दूसरा बेचना चाहता है, विभाजन का कारक परिसमापन पर किसी शेयर के मूल्य पर शायद ही विचार किया जाता है जहां शेयर एक चिंता का विषय बन रहा हो। ऐसे मामलों में जहां शेयरों को उद्धृत किया जाता है और शेयर बाजार पर लेनदेन होता है, वहां मूल उपज विधि अलग नहीं हो सकती है, लेकिन जहां शेयरों को उद्धृत नहीं किया जाता है, इन बाद के मामलों में उपज को विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए जिनके बारे में पहले उल्लेख किया गया है।

यदि घोषित लाभांश में मुनाफा प्रतिबिंबित नहीं होता है और शेयरों के लिए कम कमाई वाली उपज कंपनी द्वारा दिखाई जाती है जो उस वर्ष के लिए प्रकट किए गए वित्तीय मामलों पर विचार करने पर अवास्तविक है, तो संपत्ति कर अधिकारी तुलन-पत्र का परीक्षण कर सकता है और शेयरों

द्वारा अर्जित संभावित उपज के आधार पर मूल्यांकन तय कर सकता है। यहां, इंग्लैंड में संपत्ति शुल्क अधिनियम में और कुछ अन्य राष्ट्रमंडल देशों में समान अधिनियमों में, संपत्ति-कर अधिनियम के तहत समान प्रावधान संपत्ति के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए प्रदान करते हैं जो कि संबंधित की राय में है। मृत्यु की तिथि पर खुले बाजार में बेचने पर अधिकारी को मिलेगा। ऐसे अधिनियमों के तहत परिसंपत्तियों के मूल्यांकन से निपटने में ग्रीन ऑन डेथ इयूटीज़ (छठा संस्करण) लाभांश के संदर्भ में मूल्यांकन के अलावा अन्य कारकों पर विचार करता है। पृष्ठ 407 पर यह लिखा है:-

"अक्सर नहीं, लाभांश कंपनी के मुनाफे का केवल एक छोटा सा हिस्सा दर्शाता है और बड़ी रकम आरक्षित के रूप में व्यवस्थित रूप से जमा की जाती है। इस संबंध में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि गैर-उद्धृत कंपनियों में उद्धृत शेयरों में निवेशक, विशेष रूप से लाभांश नीति के संबंध में, शेयरधारकों के हित अक्सर उन लोगों से भिन्न होते हैं जहां शेयर कुछ व्यक्तियों (विशेष रूप से एक ही परिवार के सदस्यों) के पास होते हैं, उन्हें लाभांश के रूप में इधिकतम संभव राशि का भुगतान करना जरूरी नहीं है। कंपनी द्वारा लाभ को अपने पास रखना कर योग्य लाभांश की प्राप्ति से बेहतर हो सकता है। ऐसी कंपनी में शेयरों की खरीद जो अपने मुनाफे का केवल एक छोटा सा हिस्सा वितरित करती

है, उसके लिए आकर्षक साबित होने की संभावना नहीं है एक निवेशक वर्तमान आय की तलाश में है, लेकिन खुला बाजार किसी भी तरह से ऐसे निवेशकों तक ही सीमित नहीं है। इसमें, उदाहरण के लिए, कंपनी के मौजूदा सदस्य शामिल हैं, जिनके लिए शेयर दूसरों की तुलना में अधिक मूल्यवान हो सकते हैं और जो बाहरी लोगों और अतिरिक्त कर दाताओं को बाहर करना चाह सकते हैं जिनका लक्ष्य वर्तमान आय के बजाय पूंजी की सराहना है।"

पुनः पृष्ठ 409 पर यह देखा गया है:-

"जब भी लाभांश अकेले कंपनी की लाभप्रदता का सही मायने में प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो कमाई के संदर्भ में मूल्यांकन उपयुक्त होता है। मूल्यांकन के "लाभांश" और "कमाई" के तरीके परस्पर अनन्य नहीं हैं और दोनों का उपयोग संयोजन के रूप में किया जा सकता है। जहां एक द्वारा लाया गया मूल्य दूसरे द्वारा दिखाए गए मूल्य से व्यापक रूप से भिन्न होता है, एक मध्यवर्ती आंकड़ा उपयुक्त हो सकता है

जहां एक कंपनी लाभदायक व्यवसाय में लगी हुई है, लेकिन शेयरधारक भी निदेशक हैं और लाभांश के बजाय पारिश्रमिक

के रूप में कंपनी से जो कुछ भी उन्हें चाहिए उसे लेना पसंद करते हैं, पारिश्रमिक के माध्यम से वितरित लाभ को मूल्यांकन में ध्यान में रखा जाना चाहिए। व्यवहार में, इन मामलों में लाभांश के रूप में लाभ के उचित अनुपात (उदाहरण के लिए तुलनीय कंपनियों का औसत वितरण) के वितरण को मानकर लाभांश उपज मूल्यांकन को अपनाया जा सकता है: वैकल्पिक रूप से मूल्य का अनुमान कमाई के संदर्भ में लगाया जा सकता है। किसी भी मामले में, लाभ को सामान्य प्रबंधन शुल्क से अधिक भुगतान किए गए पारिश्रमिक को शामिल करने के लिए समायोजित किया जाएगा।"

लेकिन जहां कोई व्यक्ति ऐसी कंपनी में शेयर रखता है जो घाटे में चल रही है और जहां अस्थायी वृद्धि के रूप में रिजर्व से भी लाभांश की घोषणा करना उचित नहीं है या जहां इसकी पूंजी संरचना प्रभावित होने की संभावना है या यदि मंदी की स्थिति जारी रहती है दूसरे शब्दों में, कंपनी परिसमापन के लिए तैयार है, मूल्यांकन शेयरों का विभाजन मूल्य हो सकता है। हालाँकि, इस मामले में, हमें उन सभी बारीकियों और महत्वपूर्ण योग्यताओं और सीमाओं में जाने की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें उन मामलों में लागू करना पड़ सकता है जहां शेयरों के मूल्य तय करने में कंपनी की संपत्ति और देनदारियों को ध्यान में रखा जाना है। किसी चालू प्रतिष्ठान में

मूल्यांकन का सामान्य सिद्धांत औसत बनाए रखने योग्य मुनाफे के आधार पर उपज है, जो समायोजन आदि के अधीन है, जिसकी किसी विशेष मामले की परिस्थितियों के लिए आवश्यकता हो सकती है। सीलोन के महान्यायवादी बनाम मैकी(') में हालांकि मुनाफे में उतार-चढ़ाव और युद्धकालीन अनिश्चितताओं ने रखरखाव योग्य लाभ के किसी भी विश्वसनीय अनुमान को रोक दिया। इन असाधारण परिस्थितियों में यह माना गया कि इसके विपरीत निश्चित साक्ष्य के अभाव में एक चालू संस्था के रूप में व्यवसाय का मूल्य मूर्त संपत्तियों से अधिक हो गया। लॉर्ड रीड ने इस तर्क का उल्लेख करते हुए कहा कि तुलन-पत्र विधि को स्वीकार करने में सीलोन के सुप्रीम कोर्ट ने कानून में गलती की क्योंकि यह केवल एक विभाजन मूल्य दे सकता है जो कि व्यवसाय के मूल्य को एक चालू चिंता के रूप में खोजने के लिए आवश्यक था, जिसे पेज सं. 779 में पाया गया है:-

"यह सच है कि मृतक द्वारा धारित शेयरों का खरीददार को कंपनी में एक चालू संस्था के रूप में एक नियंत्रणकारी हित प्राप्त हो सकता था, और लॉर्डशिप्स के निर्णय में इन शेयरों के मूल्य का निर्धारण एक चालू संस्था के रूप में कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में करना सही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक स्थापित व्यवसाय का मूल्य आम तौर पर उसकी मूर्त परिसंपत्तियाँ के कुल मूल्य से अधिक होता है

और अक्सर बहुत अधिक होता है, लेकिन इसे एक वैश्विक सत्य नहीं माना जा सकता है। यदि किसी विशेष मामले में यह साबित हो गया है कि प्रासंगिक तिथि पर व्यवसाय को उसकी मूर्त संपत्ति के मूल्य से अधिक पर नहीं बेचा जा सकता था, तो इसे एक चालू संस्था के रूप में इसका मूल्य माना जाना चाहिए। लॉर्डशिप्स के निर्णय में इस मामले में यह साबित हो गया है कि मृतक की हिस्सेदारी सितंबर, 1940 में कंपनी की मूर्त संपत्ति के मूल्य से किसी भी अधिक कीमत पर नहीं बेची जा सकती थी।"

आयरिश मामले में स्मिथ बनाम राजस्व आयुक्त (1) जिस पर राजस्व की ओर से निर्भरता रखी गई थी मृतक और उसके बेटे के पास निजी कंपनी के सभी शेयर थे जिसका स्थानांतरण प्रतिबंधित था। यह भी पाया गया कि मृतक के पास नियंत्रक शेयर थे और यह कि पिता और पुत्र दोनों उनके द्वारा किए गए काम के लिए वार्षिक पारिश्रमिक लेते थे। पिता को प्रति वर्ष £3000 और पुत्र को प्रति वर्ष £1000 मिलते हैं। पिछले छह वर्षों के लिए लाभांश का औसत 5.3% था और उस आधार पर हालांकि शेयरों का मूल्य 15 शिलिंग तक था, निष्पादकों ने 17 एस. 6 डी. की पेशकश की। हालांकि राजस्व ने इस आधार पर शेयर का मूल्य 22 एस 6 डी तय किया कि मृतक जिसके पास एक प्रमुख मतदान शक्ति थी, वह इसे स्वैच्छिक परिसमापन में ला सकता था और इसलिए मूल्य का निर्धारण

देनदारियों पर परिसंपत्तियों की अधिकता के आधार पर किया जाना चाहिए जैसा कि इस तरह के समापन में अपनाया जाएगा। आयुक्तों द्वारा यह पाया गया कि इस तरह के व्यवसाय के लिए मृतक को प्रति वर्ष £3000 के आंकड़े पर दिया जाने वाला पारिश्रमिक उनकी सेवा के मूल्य के सभी अनुपात से बाहर था। हन्ना. जे. ने पेज सं. 654 पर पाया:

"इसमें मैं सहमत हूं, लेकिन दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं द्वारा सामने रखे गए इस दृष्टिकोण को काफी महत्व दिया जाना चाहिए कि यह एक पारिवारिक कंपनी थी।"

जहां निदेशकों, जो प्रमुख मालिक थे, के पारिश्रमिक में अधिक महत्व दिया जायेगा; और यह एक अनूठा व्यवसाय था, जिसमें दोनों निदेशकों को विशेष ज्ञान था, और जिस पर वे लगातार दैनिक ध्यान देते थे, और अधिकांश ग्राहकों के साथ उनके विशेष व्यक्तिगत संबंध थे। इनमें से किसी भी शेयर के काल्पनिक बाजार में एक खरीदार इन कारकों के मूल्य को पहचानेगा, और सामान्य पारिश्रमिक से कहीं अधिक के लिए उचित भत्ता देगा। दोनों तरफ के साक्ष्यों पर काफी विस्तार से विचार किया गया, और इस पर विचार करने के बाद मेरे हिसाब से इस कंपनी को उचित रूप से अपनी पूंजी पर वाणिज्यिक आधार पर 10 प्रतिशत कमाने

में सक्षम माना जा सकता है, और मैंने ऐसा पाया है।
लेकिन, यदि इसे मुख्य परीक्षण के रूप में लिया जाना है,
तो इसे एक तरफ, शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध, और
दूसरी तरफ, इसके कारण कंपनी की स्थिति की शानदार
सुरक्षा के लिये जोड़े गए मूल्य पर विचार करना होगा। "

यह देखा जाएगा कि यह मामला इस तर्क का समर्थन नहीं करता है
कि क्योंकि मृतक कंपनी को स्वैच्छिक परिसमापन में लाने की स्थिति में
था, इसलिए विभाजन मूल्य सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। यदि बिल्कुल
भी यह उस तर्क के विरुद्ध है क्योंकि साक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन
कंपनी की लाभ कमाने की क्षमता पर निर्धारित किया गया था। उल्लिखित
ऑस्ट्रेलियाई मामले ऑस्ट्रेलियाई संपत्ति शुल्क मूल्यांकन अधिनियम पर
आधारित हैं जिसके तहत संपत्ति का वास्तविक मूल्य जो शुल्क योग्य
संपत्ति का हिस्सा है, का पता लगाया जाना है। फिर भी, यह मैक कैथी
बनाम संघीय कराधान आयुक्त में निर्धारित किया गया था कि मृतक की
मृत्यु पर उसके द्वारा रखे गए शेयरों का वास्तविक मूल्य उस मुनाफे पर
अधिक निर्भर करता है जो कंपनी कमा रही है और उसे अपने व्यवसाय की
प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। उन
राशियों पर जो शेयरों के परिसमापन पर प्राप्त होने की संभावना होगी, और
एक उचित राशि से अधिक निदेशकों को फीस के रूप में भुगतान की गई
धनराशि को एक मालिकाना कंपनी की उचित कमाई क्षमता का निर्धारण

करते समय लाभ के रूप में माना जाना चाहिए जो एक भागीदार के चरित्र को धारण करती है। - सीमित देनदारियों के साथ जहाज व्यापार।

विलियम्स, जे. ने पृष्ठ 11 पर देखा:

".....किसी मृत व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु की तिथि पर किसी कंपनी में रखे गए शेयरों का वास्तविक मूल्य उस लाभ पर अधिक निर्भर करेगा जो कंपनी कमा रही है और उसे अपने व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बनाने में सक्षम होना चाहिए। वह रकम जो शेयरों के परिसमापन पर प्राप्त होने की संभावना होगी।"

उस मामले में यह पाया गया कि व्यवसाय को ईमानदारी की कमी के साथ संचालित नहीं किया जा सकता है, लेकिन चूंकि परिवार की महिलाओं द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, जिन्होंने कोई सेवा प्रदान नहीं की थी, स्वीकार्य नहीं था, उचित कमाई क्षमता पर पहुंचने के लिये इसे मुनाफे में जोड़ा गया था ।

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि धारा 16-ए(1)(सी) ऑस्ट्रेलियन अधिनियम ने आयुक्तों को

"उस राशि का अनुमान लगाने का विवेकाधिकार दिया है जो शेयरों के धारक को मृतक की मृत्यु की तिथि पर कम्पनी

की स्वैच्छिक समाप्ति की स्थिति में प्राप्त होने की उम्मीद की जानी चाहिए।"

उपर्युक्त प्रावधान पर विचार करते समय, संघीय कर आयुक्त बनाम सागर में न्यायाधिपति विलियम्स द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि

"..... जहां एक कंपनी एक चालू संस्था है, ऐसे उदाहरण दुर्लभ प्रतीत होंगे जिनमें पैरा(सी) का उपयोग करना उचित होगा। एक उदाहरण यह हो सकता है कि मृतक के पास पर्याप्त शेयर हों या उसका नियंत्रण हो ताकि वह एक विशेष प्रस्ताव पारित कर सके कि कंपनी को स्वेच्छा से बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर भी, जहां व्यावहारिक हो, पैरा (ए) या (बी) का उपयोग करना बेहतर प्रतीत होगा।"

लिमिटेड कंपनी के शेयरों के मूल्यांकन के विभिन्न पहलुओं की एक जांच हमें निम्नलिखित निष्कर्ष पर ले जाएगी:

(1) जहां पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत किया जाता है और उनमें लेनदेन होता है, मूल्यांकन तिथि पर प्रचलित कीमत शेयरों का मूल्य है।

(2) जहां शेयर किसी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के हैं जो स्टॉक एक्सचेंज या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उद्धृत नहीं किए गए हैं, तो

मूल्य उचित वाणिज्यिक आधार पर लाभ कमाने की क्षमता को दर्शाते हुए लाभांश के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। लेकिन जहां वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस आधार पर उपज की मात्रा शेयरों का मूल्य निर्धारित करेगी। दूसरे शब्दों में, लाभांश और कमाई आम तौर पर मूल्य निर्धारित करेगी। लाभांश और कमाई विधि या उपज विधि परस्पर अनन्य नहीं हैं; जैसा कि ऊपर बताया गया है, दोनों को लाभ कमाने की क्षमता सुनिश्चित करने में मदद करनी चाहिए। यदि दो तरीकों के परिणाम भिन्न हैं, तो अनुचित खर्चों के समायोजन और मुनाफे का उचित अनुपात अपनाकर एक मध्यवर्ती आंकड़े की गणना करनी पड़ सकती है।

(3) एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मामले में, जहां व्यय वाणिज्यिक उद्यम के सभी अनुपात से बाहर किए जाते हैं, उन्हें कंपनी के मुनाफे में वापस जोड़ा जाएगा। ऐसी कंपनियों में उपज की गणना के लिये शेयर हस्तांतरण पर प्रतिबंध को भी ध्यान में रखा जाएगा जैसा कि मूल्यांकन पर पहुंचने में पहले संकेत दिया गया था।

(4) जहां लाभांश उपज और कमाई का तरीका टूट जाता है कंपनी की मुनाफा कमाने और लाभांश घोषित करने में असमर्थता के कारण, यदि सेट बैक अस्थायी है तो सेट बैक से पहले शेयरों के मूल्य का अनुमान लगाना और आनुपातिक के अनुरूप प्रतिशत से छूट देना संभव है। उन

कंपनियों के उद्धृत शेयरों की कीमत में गिरावट, जिन्हें समान उलटफेर का सामना करना पड़ा है।

(5) जहां कंपनी समापन के लिए तैयार है तो विभाजन मूल्य पद्धति यह निर्धारित करती है कि उस प्रक्रिया से क्या प्राप्त होगा।

(6) जैसा कि सीलोन के महान्यायवादी बनाम मैकी (सुप्रा) में परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यांकन उचित होगा, जब जहां उस स्थिति में मुनाफे में उतार-चढ़ाव और मूल्यांकन की तिथि पर परिस्थितियों की अनिश्चितता संभावित लाभ और लाभांश के उचित अनुमान को रोके।

"उपरोक्त सिद्धांतों को स्थापित करने में, हमने कोई कठोर नियम बनाने की कोशिश नहीं की है क्योंकि अंततः प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, व्यवसाय की प्रकृति, लाभप्रदता की संभावनाएं और ऐसे अन्य विचारों को ध्यान में रखना होगा, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर लागू होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, बाजार मूल्य जब तक कि असाधारण परिस्थितियों में, जिनका हमने उल्लेख किया है, इस परिकल्पना पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक धारक कम्पनी को परिसमापन में ला सकता है, इसका मूल्य परिसमापन पर माना जाना चाहिए विभाजन मूल्य पद्धति, उपज विधि,

आम तौर पर लागू विधि है जबकि विभाजन मूल्य पद्धति वह है जिसका असाधारण परिस्थितियों में सहारा लिया जाता है या जहां कंपनी परिसमापन के लिए तैयार है लेकिन फिर भी यह तरीकों में से एक है।"

हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया प्रश्न उस उत्तर के दायरे को सही ढंग से इंगित नहीं करता है जो उस न्यायालय से मांगा गया था और यह सुझाव दिया गया था कि हमें प्रश्न को फिर से तैयार करना चाहिए। हमारे पास निश्चित रूप से ऐसा करने की शक्ति है जब तक कि कोई नया और अलग प्रश्न नहीं उठाया जाता है, लेकिन इसे केवल न्यायाधिकरण द्वारा या इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्न को दोबारा तय करने या फिर से तैयार करने तक ही सीमित रखें, जिसने मामले के बयान की मांग की थी। एक प्रश्न का उत्तर देने से पहले इसे दोबारा तैयार किया गया ताकि पार्टियों के बीच वास्तविक मुद्दे को सामने लाया जा सके: नारायण स्वदेशी वीविंग मिल्स बनाम कमिश्नर ऑफ़ ईपी.टी. और कुसुम बेन डी महादविया बनाम आयकर आयुक्त में उच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया प्रश्न यह मानते हुए कि उपज विधि ही लागू होने वाली एकमात्र विधि है और उस आधार पर न्यायाधिकरण को एक मामला बताने की आवश्यकता है कि क्या विभाजन मूल्य पद्धति के सिद्धांत को शामिल करने वाली विधि का पालन करना कानून में उचित था। यदि प्रश्न को पक्षों के बीच वास्तविक मुद्दे को सामने

लाते हुए दोबारा तैयार किया जाता है, जिस पर न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने प्रयास किया है तो उचित उत्तर देने में सुविधा होगी। हम तदनुसार प्रश्न को इस प्रकार पुनः बनाते हैं: -

"क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर संपत्ति कर अधिनियम की धारा 7 के तहत शेयरों के मूल्यांकन के आधार के रूप में न्यायाधिकरण द्वारा अपनाया गया विभाजन मूल्य पद्धति का सिद्धांत कानून में टिकाऊ है? यदि नहीं तो सही आधार क्या होगा ?"

1969 की पहली दो अपील 1135 और 1136 में न्यायाधिकरण द्वारा विभाजन मूल्य पद्धति अपनाई गई थी और उपज पद्धति को न अपनाने के लिए उसकी दलील यह थी कि प्रत्येक के संबंध में लाभांश की एक सूची पहली बार उसके समक्ष दायर की गई थी। कंपनियां, धन-कर अधिकारी और अपीलीय सहायक आयुक्त के साथ-साथ न्यायाधिकरण के पास प्रत्येक कंपनी की तुलन-पत्र (तुलन पत्रियां) थी क्योंकि उन मामलों में शेयरों का मूल्यांकन उन तुलन-पत्र के आधार पर विभाज्य मूल्य पद्धति पर किया गया था। यदि तुलन-पत्र दाखिल की जाती तो वे लाभांश का भी खुलासा करते क्योंकि वास्तव में मामले के विवरण से पता चलता है कि सभी कंपनियों ने वर्ष 1959-60 के लिए लाभांश घोषित किया था। अन्यथा भी, एक तथ्य अन्वेषी प्राधिकारी के रूप में न्यायाधिकरण, सूची पर विचार कर

सकता था या उन्हें आगे किसी भी जांच के लिए धन-कर अधिकारी को भेज सकता था। पिछली तीन अपीलों में न्यायाधिकरण ने उपज पद्धति अपनाई थी। परिणामस्वरूप प्रश्न के पहले भाग का हमारा उत्तर नकारात्मक है और दूसरे भाग का हमारा उत्तर पहले से निर्धारित सिद्धांतों के संदर्भ में है। 1969 की अपील संख्या 1765 से 1767 में, न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई गई विधि उचित विधि होने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा किसी मामले को बताने का निर्देश देने से इनकार करने पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। इन कारणों से सभी अपीलें जुर्माने सहित खारिज की जाती हैं। इन कारणों से, सभी अपीले सव्यय खारिज की जाती हैं। एक सुनवाई शुल्क।

याचिकाएं खारिज की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजीव कुमार बिजलानी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।